भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नी संख्या :557

जिसका उत्तिर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

557. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः

क्याy**कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 2018–19 में 615 मिलियन टन कोयले की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए सरकारी यूनिट कोल इंडिया लिमिटेड को प्रतिदिन रेलमार्ग से औसतन 288 रेकों को भेजने की जरूरत होगी;

(ख) क्या 31 अगस्त, 2019 के अनुसार औसत समग्र लोडिंग 270.8 रेक प्रतिदिन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल रेलमार्ग द्वारा कोयला ढुलाई की मांग में अचानक वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई में वृद्धि आने की संभावना कम है?

उत्तkर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): वर्ष 2018-19 के लिए नीति आयोग द्वारा कुल 991.35 मिलियन टन कोयले की मांग का अनुमान लगाया था। कोयले की स्वादेशी उपलब्धिता 732 मि.ट. होने का अनुमान था जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पावदन 606.89 मि.ट. था। वर्ष 2018-19 में सीआईएल ने 280.7 रेक/दिन के औसत रेक लदान के साथ 608.14 मि.ट. कोयले का प्रेषण किया है।

(ख): वर्ष 2019-20 (31.08.2019 तक) में सीआईएल से कोयले का प्रगामी रेक लदान 263.4 रेक प्रतिदिन रहा है।

(ग) तथा (घ): देश में दूरवर्ती स्था.नों तक कोयले की भारी मात्रा में ढुलाई के लिए रेलवे ढुलाई का एक पसंदीदा माध्य:म है। कोयले की निकासी में वृद्धि से रेलवे के माध्यकम से ढुलाई बढ़ने की संभावना है। सघन यातायात एवं इससे जुड़े पर्यावरणीय सरोकारों को ध्याान में रखते हुए सीआईएल का उद्देश्यय सड़क मार्ग के माध्याम से कोयले की ढुलाई को इष्टतम करना है।

*****